



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1572]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 6, 2014/श्रावण 15, 1936

No. 1572]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 6, 2014/SHRAVANA 15, 1936

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2014

का.आ. 2002(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 169(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा, उसमें निर्दिष्ट पंजाब समझौते के कतिपय विषयों के सत्यापन और न्यायनिर्णयन के लिए, रावी और ब्यास जल अधिकरण का गठन किया था, और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी, 1987 को केन्द्रीय सरकार को भेज दी थी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के निबंधनानुसार उक्त अधिकरण को, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हुए 19 अगस्त, 1987 को अतिरिक्त निर्देश किए थे;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट को पूरा करने में उक्त अधिकरण द्वारा किए जाने वाले बृहत कार्य को ध्यान में रखते हुए, उक्त रिपोर्ट देने की अवधि को समय-समय पर 5 अगस्त, 2014 तक बढ़ाया गया;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिकरण द्वारा यथा इंगित अंतर्वलिप्त कार्य की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उक्त अवधि को 5 अगस्त, 2014 के पश्चात् एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक समझती है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस अवधि को, जिसके भीतर अधिकरण, इस प्रकार किए गए निर्देशों पर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित कर सकेगा, 5 अगस्त, 2015 तक आगे और बढ़ाती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 905(अ), तारीख 5 अगस्त, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के अंतिम पैरा में "5 अगस्त, 2014 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर "5 अगस्त, 2015 तक" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 15/3/85—आई.टी. (बी.एम.)]

उर्विला खाती, संयुक्त सचिव (पीपी)

टिप्पण :-रावी ब्यास जल अधिकरण का गठन करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 169(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना संख्यांक का.आ. 666(अ), तारीख 10 जून, 2003 द्वारा संशोधन किया गया और उस अवधि को जिसके भीतर अधिकरण से अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय

सरकार को भेजने के लिए अपेक्षा की गई थी, समय-समय पर अधिसूचना संख्यांक का.आ. 905(अ), तारीख 5 अगस्त, 2003, का.आ. 889(अ), तारीख 5 अगस्त, 2004, का.आ. 166(अ), तारीख 4 फरवरी, 2005, का.आ. 1093(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005, का.आ. 133(अ), तारीख 3 फरवरी, 2006, का.आ. 1218(अ), तारीख 28 जुलाई, 2006, का.आ. 104(अ), तारीख 2 फरवरी, 2007, का.आ. 1112(अ), तारीख 6 जुलाई, 2007, का.आ. 212(अ), तारीख 30 जनवरी, 2008, का.आ. 1700(अ), तारीख 16 जुलाई, 2008, का.आ. 397(अ), तारीख 4 फरवरी, 2009, का.आ. 1812(अ), तारीख 23 जुलाई, 2009, का.आ. 203 (अ), तारीख 29 जनवरी, 2010, का.आ. 1920(अ), तारीख 5 अगस्त, 2010, का.आ. 250(अ), तारीख 4 फरवरी, 2011, का.आ. 1803 (अ), तारीख 5 अगस्त, 2011, का.आ. 216 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2012, का.आ. 1736(अ), तारीख 3 अगस्त, 2012, का.आ. 317(अ) तारीख 5 फरवरी, 2013 और का.आ. 2310(अ), तारीख 29 जुलाई, 2013 द्वारा बढ़ाई गई।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2014

S.O. 2002(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 14 of the Inter- State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), constituted the Ravi and Beas Waters Tribunal for verification and adjudication of certain matters of the Punjab Settlement, referred therein, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Water Resources, number S.O. 169(E), dated the 2nd April, 1986, and the said Tribunal forwarded its report to the Central Government on the 30th January, 1987;

And whereas, further references have been made by the Central Government to the said Tribunal on the 19th August, 1987, requiring explanation and guidance on the report aforesaid, in terms of sub-section (3) of Section 5 of the said Act;

And whereas, considering the enormous exercise undertaken by the said Tribunal in completing its further report, the Central Government extended from time to time the period of making the said report, till the 5th August, 2014;

And whereas, the Central Government, keeping in view the exigencies of the work involved, as pointed out by the said Tribunal, considers it necessary to extend the said period for one year after the 5th August, 2014;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 5 of the Inter- State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), the Central Government hereby further extends the period, within which the said Tribunal may forward its report on the references so made, to the Central Government till the 5th day of August, 2015, and for that purpose, makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Water Resources, number S.O. 905(E), dated the 5th August, 2003, namely :—

In the said notification, in the last paragraph, for the words, figures and letters “till the 5th day of August, 2014”, the words, figures and letters “till the 5th day of August, 2015” shall be substituted.

[F. No. 15/3/85-I.T. (BM)]

URVILLA KHATI, Jt. Secy. (PP)

Note:— The principal notification constituting the Ravi and Beas Waters Tribunal was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 169(E), dated the 2nd April, 1986 and subsequently amended *vide* number S.O. 666(E), dated the 10th June, 2003; and the period within which the Tribunal was required to forward its further report to the Central Government was extended from time to time *vide* number S.O. 905(E), dated the 5th August, 2003, S.O. 889(E), dated the 5th August, 2004, S.O. 166(E), dated the 4th February, 2005, S.O. 1093(E), dated the 4th August, 2005, S.O. 133(E), dated the 3rd February, 2006, S.O. 1218(E), dated the 28th July, 2006, S.O. 104(E), dated the 2nd February, 2007, S.O. 1112(E), dated the 6th July, 2007, S.O. 212(E), dated the 30th January, 2008, S.O. 1700(E), dated the 16th July, 2008, S.O. 397(E), dated the 4th February, 2009; S.O. 1812(E), dated the 23rd July, 2009, S.O. 203(E), dated the 29th January, 2010, S.O. 1920(E), dated the 5th August, 2010, S.O. 250(E), dated the 4th February, 2011, S.O. 1803(E), dated the 5th August, 2011, S.O. 216(E), dated the 3rd February, 2012, S.O. 1736(E), dated the 3rd August, 2012, S.O. 317(E) dated the 5th February, 2013 and S.O. 2310 (E) dated the 29th July, 2013.